F. No. 16015/1/2018-P&I
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated :25January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Monthly Summary to the Cabinet for the month of December, 2018-reg.

The undersigned is directed to circulate herewith the Monthly Summary pertaining to the Department of Fertilizers for the month of December, 2018, for information.

This issues with the approval of competent authority.

(Rekha Sharma)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To,

1. All members of Council of Ministers

Copy to :

1. Secretaries to the Govt. of India, All Ministries/Departments
2. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi-110004.
3. Sr. PPS to Secretary (F)
4. NIC for uploading on DoF website.

No. 16015/1/2018-P&I
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(Department of Fertilizers)
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated : 25 January, 2019

Subject : Monthly Summary of Dept. of Fertilizers for the month of December, 2018.

1. Overall production performance during the month :

(Fig. in 'LMT')

Product Name	Production during the month	Cumulative production upto the month
Urea	21.34	177.62
DAP	3.13	25.90
Ammonium Sulphate (A/S)	0.49	3.61
Complex Fertilizers	7.64	68.57
Single Super Phosphate	2.75	31.56

Source mfms.nic.in as on 4.01.2019

2. Assessed Requirement, Availability and Sales of fertilizers during the month :

(Fig. in 'LMT')

Product Name	Assessed Requirement	Availability	Sale
Urea	33.07	37.68	33.68
DAP	9.08	13.69	5.13
MOP	3.12	4.57	1.99
Complex	8.78	18.30	6.72

Source of data is iFMS

3. Details of Imported Finished Fertilizers during the month:

Product Name	Quantity in 'LMT'
Urea	11.39
MOP for Agriculture use	1.15
DAP	3.50
NPK	0.00

4. Revival of Ramagundam Unit:

Ramagundam unit of FCIL is being revived on nomination basis by consortium of PSUs namely Engineers India Limited (EIL), National Fertilizers Limited (NFL) and FCIL by setting up a gas based fertilizer plant of 1.27 MMTPA capacity. As on 31st December, 2018, 93.4 % of physical progress of the project has been made. The project is likely to be commissioned in FY 2019-20.

5. Policy on Promotion of City Compost :

The sale of city compost by Fertilizer Marketing companies in December, 2018 was about 22009.05 MT and cumulative sales of city compost during 2018-19 (April, 2018 to December, 2018) are about 143743.41 MT. The sale of city compost in bulk by compost manufacturers in December, 2018 was about 8997.48 MT and cumulative sales of city compost in bulk during 2018-19 (April, 2018 to December, 2018) are about 96241.67 MT.

6. Expenditure position:

As against an available budget of Rs. 73450.35 Crore for F.Y. 2018-19, expenditure on administration of fertilizer subsidy between April-December 2018 was Rs. 60389.88 Crore (P&K : Rs. 22425.76 Crore, Urea: 37958.03 Crore & Exp. on DBT professional & office Expenses 6.09 Crore) i.e. 82.22 % of the total allocation. The matter of additional budget provisioning and special banking arrangement to meet DBT payments etc. has already been taken up with the Department of Expenditure and is of crucial importance.

7. Submission of Cabinet Note:

(i) **FACT Land sale to Govt. of Kerala :** As per directions of PMO given in the meeting held on 10.08.2018, the proposal for sale of FACT land to Government of Kerala has been delinked from the restructuring proposal and has been circulated for Inter-Ministerial consultation on 05.12.2018.

(ii) **MFL Restructuring:** As per directions of PMO given in the meeting held on 10.08.2018, the proposal for sale of land to CPCL is under examination. NOC from Government of Tamilnadu has been received. Updated circle rate of MFL land is awaited from Government of Tamilnadu for further action in the matter.

(iii) Non revival of Haldia unit: Final copies of the CCEA Note were forwarded to the Cabinet Secretariat on 26.07.2018. The proposal for handing over of HFCL land at Haldia to KoPT was delinked from the CCEA Note and has been taken up separately as per Cabinet Secretariat's directions in consultation with Department of Expenditure.

******

सं. 16015/1/2018-पीएण्डआई

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 25 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल के लिए माह दिसम्बर, 2018 का मासिक सार-एतद्संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को उर्वरक विभाग के संबंध में दिसम्बर, 2018 माह का मासिक सार एतदद्वारा सूचनार्थ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

रे० शा०

(रेखा शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
3. सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. एनआईसी को उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

सं. 16015/1/2018-पीएण्डआई

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 25th जनवरी, 2019

विषय: माह दिसम्बर, 2018 के संबंध में उर्वरक विभाग का मासिक सार।

1. माह के दौरान समग्र उत्पादन निष्पादन:

(आंकड़े लाख मी.टन में)

उत्पाद का नाम	माह के दौरान उत्पादन	इस माह तक संचित उत्पादन
यूरिया	21.34	177.62
डीएपी	3.13	25.90
अमोनियम सल्फेट (ए/एस)	0.49	3.61
मिश्रित उर्वरक	7.64	68.57
सिंगल सुपर फॉस्फेट	2.75	31.56

स्रोत : 04.01.2019 को mfms.nic.in

2. माह के दौरान उर्वरकों की आकलित आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री:

(आंकड़े लाख मी.टन में)

उत्पाद का नाम	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
यूरिया	33.07	37.68	33.68
डीएपी	9.08	13.69	5.13
एमओपी	3.12	4.57	1.99
मिश्रित	8.78	18.30	6.72

आंकड़ों का स्रोत iFMS है।

3. माह के दौरान आयातित तैयार उर्वरकों का ब्यौरा:

उत्पाद का नाम	मात्रा लाख मी.टन में
यूरिया	11.39
कृषि उपयोग हेतु एमओपी	1.15
डीएपी	3.50
एनपीके	0.00

4. रामागुण्डम इकाई का पुनरुद्धार:

एफसीआईएल की रामागुण्डम इकाई का पुनरुद्धार पीएसयूज के एक परिसंघ नामत: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और एफसीआईएल द्वारा 1.27 एमएमटीपीए क्षमता के गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करके नामांकन आधार पर किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2018 तक परियोजना की वास्तविक प्रगति 93.4% हुई है। परियोजना को वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू किए जाने की संभावना है।

5. शहरी कंपोस्ट के संवर्धन पर नीति:

दिसम्बर, 2018 में उर्वरक विपणन कंपनियों द्वारा शहरी कंपोस्ट की बिक्री लगभग 22009.05 मी.टन थी और 2018-19 के दौरान (अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक) शहरी कंपोस्ट की संचयी बिक्री लगभग 143743.41 मी.टन है। कंपोस्ट विनिर्माताओं द्वारा दिसम्बर, 2018 में शहरी कंपोस्ट की थोक में की गई बिक्री लगभग 8997.48 मी.टन थी और 2018-19 के दौरान (अप्रैल 2018 से दिसम्बर, 2018 तक) शहरी कम्पोस्ट की थोक में संचयी बिक्री लगभग 96241.67 मी.टन हुई है।

6. व्यय की स्थिति:

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 73450.35 करोड़ रुपये के उपलब्ध बजट की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2018 के बीच उर्वरक राजसहायता के क्रियान्वयन पर 60389.88 करोड़ रुपये (पीएण्डके : 22425.76 करोड़ रुपये, यूरिया : 37958.03 करोड़ रुपये और डीबीटी व्यावसायिक एवं कार्यालय व्यय 6.09 करोड़ रुपये) व्यय हुए थे अर्थात कुल आवंटन का 82.22% व्यय हुआ था। डीबीटी के भुगतान आदि के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान और विशेष बैंकिंग व्यवस्था करने का मामला पहले ही व्यय विभाग के साथ उठाया जा चुका है और यह आवश्यक महत्व का मामला है।

7. मंत्रिमंडल नोट की प्रस्तुति:

(i) **केरल सरकार को फैक्ट की भूमि की बिक्री:** 10.08.2018 को हुई बैठक में पीएमओ द्वारा दिए गए निर्देशानुसार केरल सरकार को भूमि की बिक्री के प्रस्ताव को पुनर्गठन के प्रस्ताव से अलग कर लिया गया है और अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु 05.12.2018 परिचालित किया गया है।

(ii) **एमएफएल का पुनर्गठन:** 10.08.2018 को हुई बैठक में पीएमओ द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सीपीसीएल को भूमि की बिक्री के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। तमिलनाडु सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है। मामले पर आगे की कार्रवाई हेतु एमएफएल की भूमि की अद्यतन सर्कल दर तमिलनाडु सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(iii) **हल्दिया इकाई का पुनरुद्धार न किया जाना:** अंतिम रूप दिए गए सीसीईए नोट की प्रतियां 26.07.2018 को मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित की गई थीं। हल्दिया में एचएफसीएल की भूमि को केओपीटी को सौंपे जाने का प्रस्ताव सीसीईए नोट से अलग कर लिया गया है और उसे मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देशानुसार व्यय विभाग के परामर्श से पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

******